निर्माण विभाग में तथा रेल-पथनिरीक्षण विभाग में भी असाधारण छंटनियों की व्यवस्था की गई है, जिससे बेकारी बढ़ेगी, परिचालन में सुरक्षा तथा सुविधाओं में कटौती होगी तथा अनावश्यक मजदूर आन्दोलनों की सृष्टि होगी । इस बचत को अन्य प्रकार से भी पूरा किया जा सकता है, जिस पर माननीय रेल मंत्री महोदय का ध्यान अभी तक आकृष्ट नहीं हो पाया है । आम तौर पर रेलवे के हर एक मंडल में लगभग 300 से 450 तक इन्सपैक्टरों की व्यवस्था होती है, जिन पर वार्षिक 30 लाख से 45 लाख तक हर मंडल में खर्च किया जाता है । ये कर्मचारी केवल अफ़सरों और कर्मचारियों के बीच एक दूरी कायम रखने में सहायक होते हैं । आतंक, भ्रष्टाचार, उत्पीड़न तथा आवर्जक (नकारात्मक) प्रशासन के पृष्ठ-पोषक होते हैं तथा सुपरवाइज़रों और अफ़सरों को कर्मचारियों से सीधा सम्बन्ध रख कर स्वयं काम की देख-रेख करने से बचाते हैं । इनमें से अनावश्यक संख्या घटा कर रेल प्रशासन लगभग बीस लाख रुपये सालाना की बचत कर सकता है या कर्मचारियों को अधिक सहूलियतें दे सकता है । आम तौर पर प्रत्येक मंडलीय कार्यालय में तथा विशेष तौर पर रेल के मुख्यालयों और रेल मंडल, अनुसंधान अभिकरण और मानक संगठन तथा अन्य सम्बन्धित कार्यालयों में अनावश्यक सहायक अफ़सरों, विशिष्ट अधिकारियों, वरिष्ठ अधिकारियों आदि की एक अच्छी खासी फ़ौज खड़ी कर रखी गई है, जो आंकड़ों के भ्रम जाल में डाल कर सरकार पर अनावश्यक व्यय-भार बढ़ा रही है । माननीय रेल मंत्री महोदय को प्रशासनिक सुधार समिति का इस ओर ध्यानाकर्षण कर के इस मद में कम से कम चार करोड़ रुपये प्रति-वर्ष बचत का प्रबन्ध करना चाहिए। रेल के मुख्यालयों, रेल मंडल के तथा अधीनस्थ (जैसे मानक संगठन) कार्यालयों में वातानुकूलन तथा तड़क-भड़क की व्यवस्था इस असम्पन्न देश पर एक अत्यन्त अनुचित व्यय-भार की सृष्टि करती है, अतः इसमें भी कटौती की जानी आवश्यक है ।

17·09 HRS.

A STATEMENT *RE*: OCCUPATION OF AN INDIAN ISLAND *KUCHCHATIVU*) BY CEYLON

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF PLANNING AND MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRIMATI INDIRA GANDHI): Mr. Speaker, Sir, on Friday the 1st March, I promised to make a further statement to this House regarding the Kuchchativu Island.

Hon. Members might recall that in the past, questions concerning this Island have been asked in both Houses of Parliament. As was stated in reply to Question No. 896 in the Lok Sabha on the 30th August, 1960, (and I quote) "there is some controversy between us and the Ceylon Government as regards jurisdiction over the Island" (Unquote). Fishermen from India and Ceylon use the Island during the fishing season which lasts from February to April. There is a small Church which Catholic pilgrims from India and Ceylon visit every year during Saint Anthony's festival in March. Saint Anthony is the patron Saint of fishermen.

Our High Commissioner called on the Hon'ble Prime Minister of Ceylon and last week our External Affairs Ministry also called the High Commissioner of Ceylon in Delhi. I have now received a message from the Hon'ble Prime Minister of Ceylon both through our High Commissioner in Colombo and the Ceylonese High Commissioner in Delhi that he is agreeable to any matter concerning Kuchchativu being discussed in accordance with the procedure laid down during my meeting with him in September last year. Hon'ble Member will recall that it was agreed then that "senior officials of the two Governments should meet once a year alternately in Colombo and New Delhi to review the progress of India-Ceylon relations in all fields and exchange views on other matters of common interest". We appreciate this friendly approach and propose to discuss this in accordance with the above procedure, which appears adequate to deal with the situation both in our opinion and in the opinion of the Ceylon Government.

[Shrimati Indira Gandhi]

It is proposed to discuss the question of this Island with the Government of Ceylon in the near future. Bearing in mind our fraternal relations with Ceylon and the fact that we have settled several difficult problems with them in a peaceful and friendly manner, I have every hope that this question also can be settled in a similar manner.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर) : वक्तव्य में यह नहीं बताया गया कि क्या श्रीलंका ने इस टापू पर कब्जा कर लिया है, इसके बारे में यह चुप हैं।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : न यही बताया कि अब क्या स्थिति है।

MR. SPEAKER: If I allow some questions now, that will be going against the procedure. If you want you can have a discussion for half an hour or one hour where everybody will have a chance. That has been the normal procedure that we have been following. One hour's discussion will be all right where each one of you, Congress Members also, will be able to talk about it. I have no objection to that. But if in a confusing way we put some questions, it will not serve the purpose. Tomorrow we are meeting where the Minister of Parliamentary Affairs and most of you will be there. There are so many things pending and you will have to fix the priorities. For the present, once we begin, I do not know where it will lead to because I cannot prevent any hon. Member from asking questions. I would appeal to you to have a discussion. I shall be allowing the discussion.

SHRI MANUBHAI PATEL (Dabhoi): We would like to know the exact name of it.

17·13. Hrs.

RAILWAY BUDGET—GENERAL DISCUSSION—*contd.*

MR. SPEAKER: Shri Bajpai may now resume his speech and finish in five minutes.

श्री विहारी वाजपेयी : रेल का निर्माण विभाग सूक्ष्म होते हुए भी निर्माण कार्य के लिए ठेकेदारों की एक विशाल संख्या रखने से काम के नैतिक स्तर में ह्रास हुआ है। तथा भ्रष्टाचार में वृद्धि हुई है, अतः माननीय रेल मंत्री महोदय को इस ओर भी ध्यान देने का कष्ट करना चाहिए जिससे रेल विभाग को लगभग 7 करोड़ रुपया वार्षिक की बचत हो सकती है। एक ओर अच्छे खासे सतर्कता विभाग की व्यवस्था तथा दूसरी ओर लाखों की संख्या में कर्मचारियों का प्रति वर्ष स्थानान्तरण, इस देश के निरीह करदाता पर एक अनावश्यक व्यय-भार में वृद्धि करता है, अतः इनमें भी सुधार की योजना बनायी जानी चाहिए। प्रति वर्ष भारी भरकम स्पेशल ट्रेनें ले जा कर बड़े अफसरों के निरीक्षण तथा उसके पूर्व होने वाली टीम टाम में भी प्रतिवर्ष कम से कम 20 लाख रुपये व्यर्थ खर्च किए जाते हैं। प्रथम श्रेणी की व्यवस्था में कटौती करके रेल के अफसरों को जो भारी भरकम सैलून दिये गये हैं इनको भी यात्री गाड़ियों में परिवर्तित करके लगभग 2 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की बचत की जा सकती है। माननीय रेल मंत्री महोदय को एक संसदीय समिति इस विषय में आवश्यक छानबीन तथा परामर्श के लिए भी नियुक्त करनी चाहिए जो वास्तविक बचत के साधनों की ओर इंगित कर सके तथा इस प्रकार उपलब्ध साधनों का यात्री सुविधा या कर्मचारी कल्याण के कार्यों में सदुपयोग किया जा सके।

रेलवे प्रशासन के संगठित तथा असंगठित श्रमिक वर्ग के साथ तत्संबंधों में भी इस वर्ष ह्रास ही दिखाई दिया है। उदाहरणार्थ गत 1967 में उत्तर रेल के जनरल मैनजर महोदय का वार्षिक निरीक्षण केवल इलाहाबाद टूंडला तथा वाराणसी व फैजाबाद स्टेशनों तक ही सीमित रह गया, क्योंकि उनके अपने कर्मचारियों से सम्बन्ध अच्छे नहीं रहे। अकेले लखनऊ मंडल में ही इस वर्ष तीन बार सामूहिक सत्याग्रह या भूख हड़ताल तथा चार प्रदर्शन एक मान्यता प्राप्त श्रमिक संगठन ने किये जिसे वार्तालाप तंत्र तथा ह्विटले कौंसिल की व्यवस्थायें भी प्राप्त हैं। लगभग 11 सुव्यवस्थित तथा सर्वथा अनुशासित प्रदर्शन